दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों और श्रोताओं के बारे में सर्वेक्षण

*311. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्रमश: दर्शकों और श्रोताओं का कोई सर्वेक्षण किया गया है या किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्शकों और श्रोताओं का अनुपात क्या है ;

(ग) सरकार दर्शकों और श्रोताओं की रुचि के अनुरूप कार्यक्रम बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों की समितियों में क्रमश: दर्शकों और श्रोताओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में दर्शक सर्वेक्षण मार्च, 1990 में और आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में श्रोता सर्वेक्षण 1990–91 में किया गया था । इन सर्वेक्षणों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शकों और श्रोताओं का अनुमानित अनुपात इस प्रकार है :—

प्रतिशत

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीणक्षेत्र
दूरदर्शन	88.00	75.00
आकाशवाणी	88 90	93.00

(ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के फिक्सड प्वाइंट चार्टों में दर्शकों/श्रोताओं की रुचि और पसंद के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं ।

(घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों में समय-समय पर गठित कार्यक्रम सलाहकार समितियों में विभिन्न पक्षों के लोगों को लिया जाता है ।

Computer applications in Urdu studies and Research

*312. SHRI MOHAMMED AFZAL *ALIAS* MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of projects funded for computer applications in Urdu Studies and Research;

(b) theUrdu Institutions which have been identified for computer based Education and Research in Urdu and what is the amount given to each institution;

(c) what is the mechanism for coordinatinp and facilitating exchange of research contribution from these institutions;

(d) whether these centres are connected through computer network, if so, the details thereof; and

(e) if not, which existing educational computer network can be made accessible to these institutions and at what costs and what concrete promotional efforts have been made in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) The Departmen of Electronics has initiated a project on the Technology Development for Indian Languages (TDIL under which several projects have been initiated for applications of computers in Indian Languages. This programme will cover the development of requisite technology for information processing in Urdu language also. However no specific proposals for computer applications in Urdu Studies & Research have been received so far.

The Graphics and Intelligence based Script Technology (FIST) developed by the Centre for Development of Advanced Computing (CDAC), an autonomous Society under the Department of Electro

nics provides capability for Urdu interface with computers.

(b) to (c) Do not arise.

गुजरात की विकास योजनाएं

*313. श्री राम सिंह राठवा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विकास के लिए कुछ योजनाएं योजना आयोग को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन में से प्रत्येक योजना पर क्य कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) :(क) और (ख) सिंचाई क्षेत्रक के अंतर्गत गुजरात की पांच आधुनिकीकरण स्कीमें योजना आयोग में लंबित पड़ी हैं, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

स्कीम	लागत (करोड़ रु.)	लाभ (1000 हैक्टेयर)
1. खड़ीकट नहर सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण .	8.10	2.40
2. दांतीवाड़ा जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	34.88	10.84
3. भादर परियोजना का आधुनिकीकरण . .	18.60	3.78
4. शत्रुजी सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण .	26.68	8.95
5. फतेहवाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण .	24.76	13.17

(ग) योजना आयोग में उपर्युक्तस्कीमों के लिए निवेश स्वीकृति का निर्माण राज्य सरकार की समग्र संसाधन उपलब्धता और आठवीं योजना (1992–97), जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, में गुजरात सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों के लिए दी गई क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

Fertilizer factories flouted pollution control norms

*314. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that pollution control norms are flouted by several fertilizer factories in the country both in the public and private sector by discharging dangerous effluents into the nearby river/sea waters; and

(b) whether Government have identified these fertilizer units, if so, what action has been taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a and (b) Of the 39 major nitrogenous and phosphatic fertilizer producing units in the country, 18 are complying fully with the prescribed pollution control standards, the rest-which are both in public and private sectors—are doing so to a large extent but are not able to meet the standards in respect of some pollutants. Necessary pollution control schemes have been initiated by these units. The question of action does not arise, for the present, as these units are within the time limit allowed for conforming to the prescribed standards.